(ग) यदि हां, तो क्या सरकार नई कृषि और नागरिक उपभोक्ता आपूर्ति नीति बनाने का विचार रखती हैं; और

(घ) उक्त नीति कब तक तैयार हो जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल) : (क) से (घ) कृषि नीति में अधिक पैदावार देने वाली किस्मों, सिंचाई का विस्तार तथा आधुनिक आदानों का उपयोग पर आधारित वृद्धि जिसमें महत्वपूर्ण जिंसों के मामले में उत्पादक को न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन दिया गया हैं, पर अब तक मुख्य बल दिया जाता रहा हैं। कृषि के सतत विकास को बढ़ावा देने तथा आर्थिक उदारीकरण और विज्ञान व प्रौद्योगिकी एवं प्रगति के परिणामस्वरूप विकसित नये अवसरों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए कृषि संबंधी एक विस्तृत राष्ट्रीय नीति निरूपण के अन्तिम चरणों में हैं। खुले बाजार मूल्यों को उदार बनाने के लिये सरकार की नीति के एक साधन के रूप में तथा कुछ आवश्यक जिंसों की उपलब्धता आसानी से प्रदान किये जाने वाले मूल्यों पर सुनिश्चित करके सातवें दशक के मध्य में एक सार्वजानिक वितरण प्रणाली भारत में शुरू की गई थी। वर्षो के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को सेवा प्रदान करने में असफलता, इसका शहरी पक्षपात, उन राज्यों में नगण्य कवरेज जहां ग्रामीण निर्धन का आबादी धनत्व सबसे अधिक हैं, तथा आपूर्ति के लिये पारदर्शी तथा जिम्मेदार व्यवस्था के अभाव से सम्बन्धित मामलों में सार्वजानिक वितरण प्रणाली की अत्यधिक आलोचना हुई हैं। इसे महसूस करते हुए सरकार ने लक्षित सार्वजानिक वितरण प्रणाली शुरू की हैं जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी के लिये प्रत्येक अभिज्ञात परिवार को प्रतिमाह प्रति परिवार 10 किग्रा. खाद्यान्न की दर पर विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्रदान किया जाता हैं।

Food and Agro-Industries Management Policy

312. SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA:
SHRI KAPIL SIBAL:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a sub committee constituted under convenership of Nusli Wadia has submitted a report on food and agro-industries management policy;

(b) if so, the date on which the said report was-received by the Government togetherwith the details of suggestions made in this report;

(c) whether a final decision has been taken by Government to implement these suggestions; and

(d) if so, the details thereof; and if no, decision has been taken, the reasons for delay in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (d) A sub group in the nature of a Task Force on Food and Agro-Industries Management Policy was constituted by the Prime Minister's Office (PMO), in pursuance of the proceedings of the first meeting of the Prime Minister's Council on Trade and Industry held in September, 1998. The Task Force submitted its report on 14th December, 1998. The major suggestions made by the Task Force relate to increasing food production, utilizing and marketing the food produced and creating an enabling environment for promoting food and agro-industries through realignment of tax framework, restructuring administrative framework and promoting safety and quality of food and focus on exports. These suggestions have been remitted to the Ministries concerned for initiating appropriate action on the issues relating to them.

गो-हत्या पर प्रतिबंध

313. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गो-हत्या पर प्रतिबंध लगाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) पिछले तीन वर्षो के दौरान गो-मांस के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

< कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल) : (क) से (ग) गोपशु के संरक्षण और परिरक्षण का मामला संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य की सूची में हैं। अधिकांश राज्यों ने गाय और उसकी संतति के वध पर प्रतिबंध अथवा रोक लगाने के लिए कानून बनाए हैं।

(घ) गोमांस के निर्यात पर प्रतिबंध हैं। इसलिए गोमांस के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रश्न नहीं उठता।

Foodgrain Production

314. DR. B. B. DUTTA: Will the PRIME MINISTER be pleaded to state:

(a) the growth rates achieved in the production of foodgrain during last ten years;

(b) whether these growth rates were below the target fixed for production of foodgrains during these years;

(c) what are the reasons for low growth rates in foodgrains productions;

(d) how this problem has been addressed in the Ninth Five Year Plan; and

(c) what special measures have been taken with special reference to the North Eastern Region?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) The targetted and actual production as well as their annual growth rates during last ten years are given in the enclosed Statement, (see below).

(c) and (d) The production of foodrain is subject to influence of a number of biotic, abotic and other environmental factors including adoption of crop production technologies by farmers. Food crops are grown under a diverse agro-climatic conditions which lead to fluctuations in production and productivity. The national agenda for governace envisages improving rainfed farming, improvement of degraded land, development of minor irrigation sources, improvement of drainage together with development of infrastructure, increased flow of credit by strengthening cooperative institutions and adequate marketing support.

(e) The special measures taken in North-Eastern region include undertaking of various major and medium irrigation projects, a number of minor irrigation schemes to exploit ground water, river lifts and small diversions. Short-term measures for flood control are being implemented in Assam through embark-ment of Brahamaputra. Besides, a number of ongoing multi-purpose schemes/minor irrigation schemes are being implemented in Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura.

Statement

Targets and Achievements in Production during 1987-88 to 1997-98

Year	Foodgrains production (Million Tonnes)		Growth Rates (Percentage)	
	Target	Actual	Target	Actual
1987-88	160.00	140.35	4.11	21.07
1988-89	166.57	169.92		
1989-	175.00	171.04	5.06	0.66
90	176.50	176.39	0.86	3.13
1990-91				